

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक लेखा एवं हकदारी,  
उत्तराखण्ड  
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला,  
देहरादून

न्याय अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 16 जुलाई, 2010

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989, ऑल इण्डिया जजेज एसोशियेशन व अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में योजित आई0ए0 संख्या- 244/2009 में पारित आदेश दिनांक 4-5-2010 के अनुपालन में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 635/न्याय/मुख्य/2006 दिनांक 21.06.2010 जो अपर सचिव, वित्त को संबोधित एवं अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन को पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा जो उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का जो अनुरोध किया है उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा चाही गई पृच्छा के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है-

1- अवकाश यात्रा सुविधा : मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं शासनादेश दिनांक 21.05.2010 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दिनांक 01.01.2006 से

पुनरीक्षित किये गये हैं। चूंकि न्यायिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते दिनांक 01.01.2006 अर्थात् कलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ से पुनरीक्षित किये गये हैं अतः अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु ब्लाक वर्ष की गणना भी कलेण्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी।

2- अतिरिक्त प्रभार भत्ता : इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 21.05.2010 में प्रयुक्त शब्द 'वर्तमान में शासनादेश संख्या- 54-एक (1)/XXXVI(1)/2006-06- एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था यथावत लागू रहेगी' का अभिप्राय व्यवस्था का यथावत रहने से है न कि वेतनमान के दर से। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं शासनादेश दिनांक 21.05.2010 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को अनुमन्य वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं। अतः अतिरिक्त प्रभार भत्ता की गणना निःसंदेह पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार ही की जायेगी।

3- जहाँ तक एल0एल0एम0 डिग्री धारकों को तीन वेतन वृद्धियां दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण दिये जाने का प्रश्न है उक्त स्पष्टीकरण अलग से दिया जायेगा।

भवदीया,

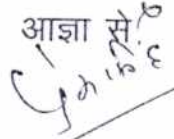
(श्रीमती इन्दिरा आशीष)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 153 / xxxvi(1)/2010-50 / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिबधक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड।

7. अध्यक्ष सहकारिता अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, हरिद्वार रोड देहरादून।
9. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, देहरादून।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
11. निबन्धक, राज्य लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
12. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
14. अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
15. सदस्य सचिव, राज्य विधिक प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
18. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की।
- ✓ 19. निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र (N.I.C.) देहरादून।
20. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
21. अपर सचिव, वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु-7, उत्तराखण्ड शासन को निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 635/न्याय/मुख्य/2006 दिनांक 21.06.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ।
22. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
  
 (प्रेम सिंह खिमाल)  
 अपर सचिव